IJAER/ Jan-Feb 2023/Volume-12/Issue-1 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

जेलों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ

Dr. Shaily Chaudhary

Assistant professor, Department of Sociology

Constituent Government College Mirapur Bangar (Bijnor). Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University Bareilly.Uttar Pardesh

सार

जेलों में रहने की अवधि और अपराधियों की दोबारा अपराध करने की दर, विशेष रूप से उच्च जोखिम समूह के लिए। दूसरे शब्दों में, एक अपराधी जितने अधिक समय तक जेलों में रहेगा, दोबारा अपराध करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी और इसके विपरीत भी। हालाँकि, रिहाई के बाद कुसमायोजन और पुनरावृत्ति की इस समस्या का मूल कारण जेलों के लॉक-अप पैटर्न और सामग्री में खोजा जा सकता है। भारत की अधिकांश जेलों में, रिमांड और दोषी आबादी; कारावास के लिए मानक न्यूनतम नियम (एसएमआर)4 के अनुसार छोटे और गंभीर अपराधियों, छोटे और बड़े कैदियों को व्यवस्थित रूप से अलग-अलग कोठरियों में नहीं रखा जाता है, जो बताता है कि कैदियों को उनकी विभिन्न श्रेणियों के अनुसार बंद किया जाना चाहिए। भारत जेलों को समाज में मानव संसाधनों की बर्बादी के लिए एक वास्तविक अवसर के रूप में पहचाना गया है।

मुख्य *जेलों में आने वाली चुनौतियाँ, कुसमायोजन और पुनरावृत्ति की इस समस्या*

प्रस्तावना

महिला और बाल विकास मंत्रालय

महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास हेतु अत्यधिक अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में की गई थी। इस विभाग को 30 जनवरी, 2006 से मंत्रालय के रूप में स्तरोन्नत कर दिया गया है।

विज़न

हिंसा से मुक्त वातावरण में सम्मान के साथ रह रहीं तथा देश के विकास में पुरुषों के समान भागीदारी निभा रहीं सशक्त महिलाएँ और सुसंपोषित बच्चे, जिन्हें शोषण-मुक्त वातावरण में विकास एवं वृद्धि के सभी अवसर प्राप्त हों।

मिशन

विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के विकास संबंधी सरोकारों को मुख्यधारा में जोड़कर, महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा महिलाओं के संपूर्ण विकास हेतु उन्हें संस्थागत एवं कानूनी समर्थन प्रदान कर उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।

नीतिगत पहल

बच्चों के समग्र विकास के लिये मंत्रालय द्वारा अनुपूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच, रेफरल सेवाओं तथा स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा को शामिल करके सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराते हुए समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) नामक विश्व का सबसे बड़ा तथा अद्वितीय आउटरीच कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

मंत्रालय 'स्वयंसिद्धा' का भी क्रियान्वन कर रहा है जो महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये एक समेकित स्कीम है। इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों का कारगर समन्वयन तथा प्रबंधन किया जा रहा है।

मंत्रालय के अधिकांश कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किये जाते हैं। इस प्रकार गैर-सरकारी संगठनों की अधिक कारगर भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाते है।

मंत्रालय द्वारा हाल ही में आरंभ की गई प्रमुख नीतिगत पहलों में आईसीडीएस तथा किशोरी शक्ति योजना का सर्वसुलभीकरण, किशोरियों के लिये पोषण कार्यक्रम शुरू करना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित करना शामिल है।

भारत जेल प्रणाली की समस्या

भारत जेलों में कुछ समस्याएं काफी हद तक व्याप्त हैं, जिन्हें कई अध्ययनों ने सुधारात्मक संस्था के रूप में प्रणाली की अपर्याप्तता का कारण बताया है। विभिन्न मामलों में, सामान्य तौर पर भारत जेलों में जीवन इस हद तक अत्यधिक व्यवस्थित है कि कैदियों की लगभग सभी गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण होता है। यह अक्सर कैदियों को मानसिक रूप से क्रूर तरीके से टूटे हुए शरीर और आत्मा के साथ छोड़ देता है, जो व्यक्तियों को नष्ट कर देता है। इस संबंध में, यह स्पष्ट है कि भारत में जेल प्रणाली को समुदाय के व्यक्तिगत सदस्यों को नष्ट करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो कारावास के सार को नकारता है, जो राष्ट्रीय गणना में मानव विकास की बर्बादी है। यह स्पष्ट है कि भारत की विभिन्न जेलें गलत तरीके से रिहाई की समस्या से जूझ रही हैं।

दिखाया गया है कि भारत में जेल संस्था के साथ संपर्क कम कठोर व्यक्तियों को रिहाई के बाद आपराधिक गतिविधियों में और अधिक कठोर बना देता है, साथ ही उनकी प्रवृत्ति फिर से आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की हो जाती है, जिससे पुनरावृत्ति की उच्च आवृत्ति उत्पन्न होती है। एडेटुला एट अल के अनुसार। (2010), दंडात्मक संस्थाएँ उपप्रणालियाँ; ऐसा माना जाता है कि न्याय, पुलिस, जेल यार्ड और न्याय प्रशासन के संचालन के तरीके आपराधिक व्यवहार और सेवा करने की तुलना में पुनरावृत्ति करने वालों को बढ़ावा देते हैं और बढ़ाते हैं; शारीरिक और वैचारिक सुरक्षा में विश्वास बढ़ाने के लिए पूर्व-दोषियों और मुक्त समाज के लोगों के बीच निवारण, पश्चाताप, सुधारात्मक और सुलहपूर्ण रवैया। इस स्थिति को अन्य देशों में भी मान्य किया गया है।

कैदियों में आलस्य और अपव्यय है, जबकि पुराने समय के व्यापारिक विचार और व्यवसाय लुप्त हो रहे हैं। जहां जेल प्रांगणों के भीतर मौजूदा व्यापार और कौशल अधिग्रहण केंद्र हैं, वे या तो काम नहीं कर रहे हैं या कुछ कैदियों के लिए अनुपयुक्त हैं जो अन्य व्यापार और शैक्षिक पसंद कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रियाएँ जो जेलों के पुनर्वास पाठ्यक्रम में मौजूद नहीं हैं। उदाहरण के लिए, कुछ कैदियों ने जेल में रहते हुए अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने और अपने जीवन की शैक्षणिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की क्षमता और इच्छा का प्रदर्शन किया है, जो जरूरी नहीं कि जेल में व्यावसायिक व्यवसायों से संबंधित हो। यार्ड। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि भारत जेल प्रणाली क्या करना है इसकी कमी, कार्यशाला सुविधाओं की कमी और अच्छे कौशल की कमी के कारण निष्क्रिय दिमागों का घर है, जिसे कैदी सीखना चाहेंगे।

उद्देश्य -

1. जेलों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ का अध्ययन ।
2. कार्रवाई का कार्यक्रम अच्छी तरह से करने का अध्ययन ।

मंत्रालय को आवंटित विषय

परिवार कल्याण।

महिला और बाल कल्याण तथा इस विषय के संबंध में अन्य मंत्रालयों एवं संगठनों के कार्यकलापों का समन्वयन।

महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार के संबंध में संलग्न संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों से संदर्भ में।

- प्राथमिक पूर्व शिक्षा सहित स्कूल पूर्व बच्चों की देख रेख।
- राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय पोषण कार्य-योजना तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन।
- इस मंत्रालय को आवंटित विषयों से संबंधित धर्मार्थ तथा धार्मिक अक्षय निधियाँ।
- मंत्रालय को आवंटित विषयों से संबंधित स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्द्धन तथा विकास।

सज़ा के एक पहलू के रूप में कारावास के सामान्य मुद्दे पर, प्रतिशोधवादी और निवारक दार्शनिक इस बात पर जोर देते हैं कि एक पथभ्रष्ट को उसके कार्यों के लिए भुगतान करने और उसे या दूसरों को अपराध करने से रोकने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। व्यक्तियों को पीड़ा पहुंचाने के एक औपचारिक परिप्रेक्ष्य के रूप में कारावास की सबसे उचित रूप से कल्पना की गई है, जो भारत में विभिन्न समाजों में पारंपरिक आपराधिक न्याय प्रणाली का एक पहलू रहा है, जबकि कारावास एक नुस्खा है, कारावास एक कारावास के भीतर रहने की प्रक्रिया है जिसे एक कारावास के रूप में जाना जाता है। कारागार। मैक कॉर्कल और कॉर्न (1954) के अनुसार एक जेल एक भौगोलिक स्थान में एक भौतिक संरचना है जहां कई लोग अत्यधिक विशिष्ट परिस्थितियों में रहते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं और एक अद्वितीय प्रकार के सामाजिक वातावरण द्वारा उनके सामने प्रस्तुत विकल्पों के साथ तालमेल बिठाते हैं। कई मायनों में बड़े समाज से अलग। जाहिर है, कुछ बुनियादी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जो जेल समुदाय और अन्य कुल संस्थाओं में समान रूप से मौजूद हैं, जो बड़े समाज में मौजूद नहीं हैं। जेल समुदाय अपनी विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली के साथ एक संपूर्ण डिज़ाइन का प्रतीक है जो व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक नेटवर्क कार्रवाई के आधार पर व्यक्तिगत सदस्यों के दृष्टिकोण को अच्छे या बुरे में बदलने में सक्षम है। जेल में जीवन का तरीका कैदियों की समायोजन प्रक्रियाओं के लिए साधन और तरीके प्रदान करता है। इसकी संस्कृति एक गतिशील संस्कृति है, जिसमें सभी प्रकार के मूल्य पुनर्अभिविन्यास और आंतरिककरण शामिल हैं।

भारत जेल प्रणाली की स्थापना दंड विधान के तीन रूपों के अनुसार की गई थी जो देश में एक दूसरे के साथ संचालित होते हैं; दंड संहिता और उसके साथ जुड़ी आपराधिक प्रक्रिया संहिता कैप 81 फेडरेशन 1990 (सीपीसी) के कानून; आपराधिक संहिता और संबंधित आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम कैप 80 फेडरेशन 1990 (सीपीए) के कानून और 12 उत्तरी राज्यों में शरिया दंड कानून (जो इन राज्यों के केवल मुस्लिम सदस्यों पर लागू होता है)। अपने स्थापना दर्शन के अनुसार, भारत जेल सेवा एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य वयस्क अपराधियों को दंडात्मक उपचार प्रदान करना है।

इसका महत्व समाज में अपराध को कम करने के लिए है। कारावास नीति के आधार पर, जेल यार्डों में अपराधियों के प्रबंधन के लिए जेल सेवा की स्थापना की गई थी। यह संवैधानिक कार्य भारत जेल संचालकों को निम्नलिखित का अधिकार देता है:

दोषी अपराधियों (कैदियों) को सुरक्षित हिरासत में रखें,

हिरासत में बंद कैदियों की सुनवाई का इंतजार करते रहें, जब तक कि कानून अदालतें उन्हें पेश करने के लिए न कहें

कानून अदालतों के निर्देशानुसार अपराधियों को दंडित करें

सजायाफ्ता कैदियों को सुधारें

जेल में सजा पूरी कर चुके कैदियों का पुनर्वास और पुन: एकीकरण करना (जेल प्रशिक्षण मैनुअल से उद्धरण)

भारत में जेलों की कार्यक्षमता के सवालों से उत्पन्न मौजूदा अंतर की इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, यह पेपर भारत की जेलों में मौजूद समस्याओं और उन्हें संबोधित करने के लिए क्रमिक सरकारों द्वारा शुरू की गई सुधार प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है। इन सुधार एजेंडे को किस हद तक लागू किया गया है और भारत में समग्र जेल प्रणाली पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर भी चर्चा की गई है।

एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में जेल का वैचारिक और सैद्धांतिक अवलोकन

जेल की अवधारणा सामाजिक विज्ञान विषयों में विभिन्न विद्वानों के बीच बहस का विषय रही है। इस अवधारणा को विभिन्न दृष्टिकोणों से माना गया है, जिसमें संरचनात्मक और कार्यात्मक आयाम शामिल हैं। उदाहरण के लिए, जेल को एक भौगोलिक स्थान में एक भौतिक संरचना के रूप में वर्णित किया गया है जहां अत्यधिक विशिष्ट परिस्थितियों में रहने वाले कई लोग अद्वितीय प्रकार के सामाजिक वातावरण द्वारा उनके सामने प्रस्तुत विकल्पों के साथ तालमेल बिठाते हैं। इसी प्रकार, जेल की कल्पना ऐसे स्थान पर की गई जहां लोगों को नियंत्रण की पूरी तरह से नई व्यवस्था के साथ बाकी दुनिया से अत्यधिक एकांत में रखा जाता है। विद्वानों द्वारा उन्नत उपरोक्त अवधारणाएँ इस समझ तक सीमित हैं कि जेल एक भौतिक वातावरण है, और इसे भौगोलिक या स्थानिक रूप से वर्णित किया जा सकता है।

भौतिक अवधारणा से बिल्कुल अलग, विचार के अन्य स्कूल भी हैं जो कार्य, रूपरेखा और लेबल पर आधारित हैं। कार्यात्मक दृष्टिकोण से, जेल को अपराधियों को दंडित करने के स्थान के रूप में माना जाता है, जहां समाज से निकाले गए अपराधियों को अपराधियों की आगे की आपराधिक गतिविधियों से समाज की रक्षा के लिए फेंक दिया जाता है; और पुनर्वास के लिए एक महल, और अपराधियों को उनकी रिहाई के बाद कानून का पालन करने वाला और उत्पादक बनना सिखाएं। ढांचे की दृष्टि से जेलों को एक संपूर्ण संस्था के रूप में भी देखा जाता है।

इस अवधारणा को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया। जबकि ओकुनोला एक संपूर्ण संस्था को मुक्त वातावरण या समुदाय के विपरीत एक ऐसी जगह के रूप में देखता है, जिसमें सामाजिक रूप से खारिज किए गए, पागल या मानसिक रूप से विकलांग लोगों को रखा जाता है, वहीं दूसरी ओर गोफमैन ने कुल संस्था की संकल्पना की, जहां व्यक्तियों के एक बड़े वर्ग के बीच एक बुनियादी विभाजन होता है। बाहरी दुनिया के साथ प्रतिबंधित संपर्क और रूढ़िवादी व्यवहार पैटर्न जहां सामाजिक गतिशीलता प्रतिबंधित है। फिर भी लेबलिंग के दृष्टिकोण से, जेल आवारा लोगों के लिए एक जगह है, जो बड़े समाज में सामाजिक जीवन के लिए वास्तविक खतरा पैदा कर सकता है, जो पहले से मानता है कि जेल में

प्रत्येक व्यक्ति एक आवारा और गैर-जिम्मेदार व्यक्ति है। यह हॉवर्ड (1960) की स्थिति है जिन्होंने प्राचीन यूनानी काल के दौरान प्राप्त चीज़ों के साथ अपने दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया।

शायद हॉवर्ड की यह संकल्पना "श्री" के दृष्टिकोण में पुनः जागृत हुई है। राजनीतिक नेता" कैदियों के प्रति, जिन्हें वे समाज का "कचरा" मानते हैं। योंगो ने अतीत के नेताओं द्वारा जहर के प्रति बरती गई उपेक्षाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा, ... अतीत पर सरसरी नजर डालने से पता चलेगा कि जब जनरल ओबासंजो ने फरवरी 1976 और सितंबर 1979 के बीच भारत सरकार का नेतृत्व किया, तो उन्होंने जेलों को विकसित करने के लिए बहुत कम काम किया। यदि वह इस बात से अनभिज्ञ था कि वहां कुछ भारत नागरिक थे। हो सकता है कि उनके लिए वे समाज के कलंक थे।

हालाँकि, हाल के घटनाक्रमों के साथ, जेलों के बारे में सामान्य धारणा कम से कम कुछ लोगों के मन में बदलती दिख रही है, विशेष रूप से इस गलत विचार के संदर्भ में कि जेलों में लोग समाज के कलंक हैं। नई अवधारणा, जिसका श्रेय योंगो2 को दिया जाता है, ने जेल को "सभी के लिए घर" के रूप में माना। इस विचार का मुख्य जोर व्यावहारिक और प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में निहित है, भले ही पारंपरिक विचार कुछ भी हों। उनका तर्क इस आधार पर आधारित है कि केवल दोषी ही जेलों में नहीं पाए जाते हैं, केवल कुछ कैदियों ने वास्तव में अपराध किए हैं जिनके बारे में उन पर आरोप लगाया गया है। यह भारत स्थिति के बारे में सच है जहां अधिकांश जेल प्रांगणों में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों की आबादी का भरा होना "स्वीकार्य" हो गया है।

निष्कर्ष

भारत सहित दुनिया के सभी हिस्सों में जेल संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों के लिए पुनर्वास और सुधारात्मक सुविधा प्रदान करना है जिन्होंने अपने समाज के नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया है। हालाँकि, व्यवहार में यह कहावत किस हद तक सच है, यह विवाद का विषय रहा है। ऐसे उदाहरण बहुतायत में हैं जहां भारत में जेलें पुनर्वास गृह के बजाय अपराधियों के लिए प्रशिक्षण स्थल बन गई हैं। भारत में जेलों के अंदर और बाहर जाने वाली आबादी का एक आकस्मिक अवलोकन यह मानता है कि प्रणाली में कुछ समस्याएं हैं, इसलिए जेल प्रणाली भारत में अपनी अपेक्षित भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है। इस अभिव्यक्ति के बारे में चिंता कि भारत जेलें कैदियों के जीवन और व्यवसाय पर सकारात्मक प्रभाव डालने के मामले में उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हैं, ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिन्हें अभी तक सिस्टम के कार्यों और अस्तित्व पर पूरी तरह से संबोधित नहीं किया गया है।

सन्दर्भ

1. एडेटुला जीए, एडेटुला ए, फातुसिन एएफ 2010। जेल उपप्रणाली संस्कृति: गुर्गों, दोषियों और मुक्त समाज पर इसके व्यवहारिक प्रभाव। इफ़े साइकोलॉजी। 18(1): 232-251

2. अगोमोह यूआर 1996। भारत जेलों और पुलिस कक्षों में भीड़ कम करना: रिमांड जनसंख्या के लिए व्यावहारिक रणनीतियों की एक पुस्तिका। लागोस: प्रावा।

3. अयेदोग्बो जेडी 1988. भारत जेलें: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। एक केस स्टडी के रूप में सोकोतो जेल। बी.एससी प्रोजेक्ट, अप्रकाशित। सोकोटो:

4. समाजशास्त्र विभाग, सोकोटो विश्वविद्यालय। एमनेस्टी इंटरनेशनल 2008। भारत: कैदियों के अधिकारों का व्यवस्थित रूप से उल्लंघन किया गया। लंदन: एमनेस्टी इंटरनेशनल एआई इंडेक्स: एएफआर 44/001/2008।

5. अवोलोवो ओ 1985. एडवेंचर इन पावर: माई मार्च थ्रू प्रिज़न। इबादान: मैकमिलियन पब्लिशर्स।

6. गेंड्रेउ पी, गोगिन सी, कुलेन एफटी 1999. पुनरावृत्तिवाद पर जेल की सजाओं का प्रभाव। उपयोगकर्ता रिपोर्ट: 1999-3. सुधार अनुसंधान, सॉलिसिटर जनरल कनाडा विभाग। ओटावा: लोक निर्माण और सरकारी सेवाएँ कनाडा।

7. गोफमैन ई 1961. शरण। न्यूयॉर्क: गार्डन सिटी एंकर बुक्स।

8. हावर्ड डीएल 1960. अंग्रेजी जेलें: उनका अतीत और उनका भविष्य। लंदन: बटलर एंड टार्मर लिमिटेड

9. 9. इफिओनु ओ 1987. नर्क ऑन अर्थ: अवर प्रिज़न्स एंड ड्रेडेड चैंबर्स। अफ़्रीकी कॉनकॉर्ड, 147: 14-21, जून 1987।

10. F1987 जेल कहानियां: कैदियों का अनुभव। अफ़्रीकी कॉनकॉर्ड, 147:18, जून, 1987।

11. इशका पी, अकपोववा पी 1986। कैदी स्वर्ग नहीं। न्यूज़वॉच, 4: 26. 29 दिसंबर, 1986।

12. कांगीवा जी ए 1986. सोकोतो टाउन में अपराध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। बी.एससी प्रोजेक्ट, अप्रकाशित। सोकोतो: सोकोतो विश्वविद्यालय।

13. मैक कॉर्कल एल, कॉर्न आर 1954. दीवारों के भीतर पुनर्समाजीकरण। द एनुअल्स ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 293 (1): 88-98।

14. मीक सीके 1969। भारत की उत्तरी जनजातियाँ: 1921 की दशकीय जनगणना पर एक रिपोर्ट के साथ भारत के उत्तरी प्रांतों का एक नृवंशविज्ञान संबंधी विवरण। लंदन: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

15. मेर्टन आर.के. 1949. सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना। न्यूयॉर्क: फ्री प्रेस